है । जो कि उनकी शक्ति से बाहर है । बाड़मेर, जैसलमेर, पाली एवं जोधपुर जिलों के किसानों की क्रय शक्ति बहुत ही कमजोर हो गई है जिसके कारण वे इतने मंहगे भाव में गेहूं नहीं खरीद सकते और मोटा आनाज बाजरा के भाव भी रु० 200 क्विंटल से भी अधिक बढ़ गये हैं जिसे भी वे खरीदने की स्थिति में नहीं है । किसानों में कुपोषण के कारण अनेक बीमारियों ने उन्हें घेर लिया है और वे मृत्यु के शिकार हो रहे हैं और वे भुखमरी की स्थिति में आ गये हैं । किसानों में तीव्र असंतोष है ।

अत: केन्द्र सरकार से मांग है कि राज्य की लगातार चार-पाँच वर्षों से सूखे की स्थिति को देखते हुए और तब्र मंहगाई को देखते हुए राज्य में सस्ते अनाज की दुकानें सभी ग्रामों में जहाँ प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो गेहूं मिले, को आधार रखते हुए खोली जाँए और केन्द्र द्वारा राज्य को अप्रैल माह में 60 हजार क्विंटल का कोटा दिया जावे जो मई और जून में 80 हजार और 1 लाख क्विंटल तक बढ़ाया जाए ।

श्री बी०डी० सिंह (फूलपुर) : सभापति महोदय, विभिन्न अन्वेषणों से पता चला है कि भारतवासी जो भोग्य पदार्थ उपभोग करते हैं, उनमें 25 प्रतिशत मिलावटपूर्ण होते हैं । अनेक प्रकार की बड़े पैमाने पर फैलती हुई बीमारियों का मुख्य कारण भोज्य पदार्थों में की जा रही मिलावट है । आज प्राय: सभी वस्तुएं किसी न किसी प्रकार की मिलावट की शिकार हो रही हैं, परन्तु भोज्य पदार्थों में मिलावट का जन-स्वास्थ्य पर प्रतिकुल प्रभाव विशेष चिन्ता का विषय है । विकासशील देशों में शुद्ध भोजन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वहां के अधिकांश लोग गरीब होते हैं । उनके भोजन में विटामिन आदि की कमी होती है । अस्वस्थता की दशा में अपना इलाज आदि नहीं करा पाते । भोज्य पदार्थों में रंगों की मिलावट तो तो बहुत खतरनाक हो चुकी है । कुछ समय पूर्व "टाक्सीकालोजिकल रिसर्च सेन्टर, लखनऊ" में उत्तर प्रदेश में लिये गये नमूनों की जांच की गई । 12575 रंगीन नमूनों में से 8820 नमूनों में मिलावट पाई गई । प्रयोग किये गये रंगों में ही 70 प्रतिशत मिलावट थी । रंगों में मिलावट के लिये उपभोक्ता भी उत्तरदायी है, क्योंकि रंगो के आकर्षण को वे विशेष महत्व देते हैं ।

मिलावट बहुत ही गंभीर अपराध है । विडम्बना यह है कि वर्तमान कानून के तहत अपराधियों को या तो कोई सजा नहीं मिलती या मिलती है तो नाम मात्र की । भोज्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिये 1954 में "प्रीवेन्शन ऑफ फुड एडलटेशन ऐक्ट" पारित हुआ था । समय-समय पर इस अधिनियम में संशोधन भी हुए परन्तु अब भी अधिनियम में ऐसी कमियां रह गई हैं जिससे अपराधियों को लाभ मिल जाता है । अतएव अनुभवों के आधार पर अधिनियम में आवश्यक संशोधन होना चाहिये । मात्र कानून से ही इस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता । इसके लिये जनजागरण भी आवश्यक है । अत: उपभोक्ता सुरक्षा आन्दोलन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये । सरकार इस सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कदम उठाये, जिससे मिलावट की वृद्धि को रोका जा सके तथा तत्पश्चात् धीरे-धीरे समाप्त किया जा सके ।

(vii) FINANCIAL ASSISTANCE TO THOSE AFFECTED BY THE RECENT TARNADO IN WEST BENGAL

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : A tornado ripped through some villages in Gaighata P. S. of the district of 24 Parganas (West Bengal) on April 12 last. Though the tornado was short lived, it left in its wake massive destruction. According to information available till late night of the 14th April more than 80 people were killed, 1500 injured and 6000 people rendered homeless. Some died on

[Shri Chitta Basu]

the spot, others died on way to hospital. More than 200 persons who have been fatally injured have been hospitalised. Among the dead, two were women and six children.

Speedy relief, proper rehabilitation and adequate compensation for the victims are the urgent needs. The Central Government owes its responsibility to provide financial assistance for the purposes as they are victims of natural calamity. The Prime Minister, in her magnanimity, should also grant some assistance from her relief funds.

I would also demand that the Government should immediately take necessary steps in order to provide adequate financial assistance for the purpose.

(viii) NEED TO COMPLETE VEERANAM PROJECT EARLY TO SOLVE DRINKING WATER PROBLEM OF MADRAS CITY

DR. V. KULANDAIVELU (Chidambaram) : I would like to draw the immediate attention of the House about the serious plight of the public in general in our country with special reference to my Chidambaram Parliamentary Constituency and Madras city consequent to acute water scarcity due to monsoon failures. The present water scarcity has led to the spontaneous reaction of the Railway authorites to carry water from Vijayawada to Madras and supply of water by NLC Neyveli.

The need of the hour is to make use of the available water resources in our country on a war-footing for irrigation and domicillary utility. I refer to the availability of enormous water resources in the lignite mines beds at Neyveli to meet the requirements as a long term measure. The NLC is beling out 1.8 lakh litres of water per minute from the Mines by giant bore wells all the 24 hours and this enormous water is getting wasted by unplanned diversion.

As a local Member of Parliament I have been repeatedly stressing the very need and urgency of the utilisation of the water resources for irrigation and domicillary purposes ever since my election to the Lok Sabha. I am happy to note that the present NLC Management has magnanimously responded to my earnest plea by initiating the irrigation scheme of Gangakondan lake and processing of water supply to the lakes of perurnal, Kannapuram, Kathamhai-Athanoor, Walajah, Veeranam, Willington and rivers of Sethisthope, Paravanar, Manimuthar etc. Without much financial commitments on the part of the management as a welfare measure.

At this juncture, I earnestly urge upon the Union Government to ensure revival of the feasible Veeranam Project, and avert the miseries of the millions of Madras city.

(ix) NEED FOR OPENING A BRANCH OFFICE OF EMPLOYEES-PROVIDENT FUND ORGANISATION

SHRI K. A. RAJAN (Trichur) : Trichur is the centre of the State and industrially developed area. Now, Provident Fund benefits to the employees of this area (Trichur and Palghat) are not at all received in time Only on personal contacts with the office, their grievances can be redressed in time. The employers who are meeting the entire administrative expenses of the Provident Fund offices also feel that the grievances of their employees should be dealt with without delay. This, no doubt, will act as a lubricant to the wheels of the other activities of the Provident Fund office such as settlement and loan.

Taking into account the geographical and other importance of Trichur, the Head of Employees State Insurance Corporation is situated at Trichur. For quick disposal of the Government servants' P. E. pension etc., one branch of the Accountant General's office is also functioning at Trichur. ESIC has got its own building and one five storeyed building for A. G.'s office is under construction at Trichur.